(ग) और (घ) उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए उपाय विवरण में दिए गए है।

विवरण

मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के विद्युत स्टेशनों की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उठाये गये कदम।

1. ताप विद्युत स्टेशन

संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन में प्रत्येक 210 मे० वा० वाली यूनिट 3 एवं 4 का निर्माण कार्य एम पी ई बी किया जा रहा है। यूनिट 3 और 4 को चालू करने का निर्धारित कार्यक्रम क्रमशः जून 99 और दिसम्बर 99 है;

वर्तमान में कोरबा पूर्वी टी पी एस का चरण-11 (4×50 मे० वा०) की ह्रासित क्षमता पर कार्य कर रहा है और अमरकटंक टी पी एस में चरण-1 की एक 30 मे०वा० वाली यूनिट 20 मे० वा० की ह्रासित क्षमता पर कार्य कर रही है; यूनिटों की मूल क्षमता को पुनः प्राप्त करने के लिए इन ताप विद्युत स्टेशनों में नवीकरण कार्य किया जा रहा है उपरोक्त के अतिरिक्त यूनिटों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए सरनी, कोरबा पश्चिम, कोरबा पूर्व तथा अमरकटंक टीपीएस में भी नवीकरण और आधुनिकीरण कार्य किया जा रहा है।

2. जल विद्युत स्टेशन्स

राजघाट जल विद्युत परियोजना 3×15 का बाणसागर जल विद्युत परियोजना 2 × 15 मे० वा० चरण-II , 3 × 20 मे० वा० चरण-III , 2 × 10 मे० वा० चरण IV का निर्माण कार्य एम एस ई बी द्वारा किया जा रहा है। इन यूनिटों को चालु करने की निर्धारित तिथियां नीचे दी गई हैं:—

1. बाणसागर जल विद्युत परियोजना चरण-II (2)× 15 मे० वा०)
   - (1) जुलाई 2000
   - (2) अक्टूबर 2000

   इन विद्युत स्टेशना को चालू करने का कार्यक्रम अंतिम है और बांध के शीर्ष स्तर तक निर्माण किए जाने और निधियों की उपलब्धता पर आधारित है।

2. (2) बाणसागर एच ई पी चरण-II 3 × 20 मे० वा०)
   - (1) यूनिट-I जुलाई 99
   - (2) यूनिट-II अक्टूबर 99
   - (3) यूनिट-III फरवरी 2000

3. (3) बाणसागर एचईपी चरण-IV 2 × 20 मे० वा०)
   - (1) जुलाई 2002
   - (2) अक्टूबर 2002

4. (4) राजघाट एच ई पी (3 × 15 मे० वा०)
   - (1) यूनिट-I जुलाई 1998 (अंतिम)
   - (2) यूनिट-II सितम्बर 1998
   - (3) यूनिट-III नवम्बर 1998

Power projects in Uttar Pradesh

577. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the details of power projects received from the public and private sector during the last two years in Uttar Pradesh and which of them are still pending; and

(b) by when these are proposed to be cleared?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE ON THE MINISTRY OF POWER (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) and (b) The details of proposals received from the Public and Private Sector during the last 2 years for setting up of power projects in Uttar Pradesh as on June, 1997 are as follows:

Sl. No.	Name of the Project	Sector	Capacity	Status of clearances
1.	Vishnuprayag HEP	Private	400. MW	CEA cleared.
2.	Dhauliganga (Intermediate Stage)	NHPC	210 MW	DPR under examination in CEA.

Sl. No.	Name of the Project	Sector	Capacity	Status of clearances
3.	Jawaharnagar TPP	Private	800 MW	Returned as inputs, like fuel linkage, water availability, etc., not tied up.
4.	Srinnagar HEP	Private	330 MW	Returned as inputs were not tied up.
5.	Rosa TPP	Private	567 MW	Scheme under examination.

Techno-economic clearance for the schemes 2 to 5 will be subject to the appraisal by CEA and tying up of necessary inputs/linkages by the project authorities.

Investment made in the power sector

578. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the total amount of investment made in power sector during 8th Plan period;

(b) whether Government propose to step up investment in the power sector during 9th plan;

(c) if so, the fund earmarked therefor; and

(d) the state-wise details of the investment proposed to be made in that plan period?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) The likely expenditure in the Eighth Plan in Public Sector is Rs. 76067.19 crores.

(b) to (d) The 9th five Year Plan (1997-2002) is still under finalisation in the Planning Commission. It has, however, been decided that the power sector will be funded on a priority basis.

राज्य विद्युत बोर्डों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु कदम

579. **श्री नागमणि:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्य विद्युत बोर्डों को अधिक प्रभावी बनाने एवं उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु कोई समिति बनाई गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों को असफल घोषित करके इस कार्य को निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ): (क) जी, नहीं। तथापि, भारत सरकार ने 16.10.76 तथा 3.12.86 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हुई आम सम्मति के आधार पर विद्युत हेतु एक समान न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना (सी०एम०एन०पी०पी०) का गठन करके उसके क्रियान्वयन हेतु सभी राज्य सरकारों को परिपत्रित कर दिया है। इस कार्य योजना में राज्य बिजली बोर्डों को स्वायत्तता, प्रबंधन पद्धतियों तथा रा०वि०बो० के भौतिक मानदण्डों में सुधार हेतु प्रावधान किया गया है ताकि उन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जा सके तथा अधिक सुस्पष्ट प्रणालियों को अपनाया जा सके जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हो।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।